The Economic Times (Hindi) 10 April, 2017

# अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए केंद्र ने लॉन्च किए 350 प्रोजेक्ट्स

[ पीटीआई | नई दिल्ली ]

**केंद्र सरकार** ने रविवार को 350 प्रोजेक्ट्स लान्च किए। इनमें करीब दो लाख मकान बनाए जाएंगे। इन्हें प्राइवेट सेक्टर के 38,000 करोड़ रुपये के इनवेस्टमेंट से तैयार किया जाएगा। यह केंद्र सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में कॉरपोरेट्स की ओर से पहली बड़ी पहल होगी। शनिवार को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने प्राइवेट रियल एस्टेट डिवेलपर्स के साथ एक मीटिंग की थी। मीटिंग का मकसद 'गतिरोधों' को दूर करना था ताकि '2022 तक सभी के लिए आवास' से जुड़ी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

**प्राइवेट सेक्टर करेगा 38000 करोड़ रुपये का निवेश, NCR में बनाए जाएंगे 41921 मकान**

हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलेविएशन मिनिस्टर एम वेंकैया नायडू ने गुजरात के गांधीनगर में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डिवेलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स इन मकानों को बनाने में करीब 38000 करोड़ रुपये निवेश करेंगे। इन मकानों की लागत 15 से 30 लाख रुपये की रेंज में होगी और हर मकान को बनाने की औसत लागत 18 लाख रुपये होगी। सबसे ज्यादा एक लाख मकान महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे। उसके बाद नेशनल कैपिटल रीजन में 41921 मकान, गुजरात में 28465, कर्नाटक में 7,037 और उत्तर प्रदेश में 6055 मकान बनाए जाएंगे।

## '826 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स 4 साल तक की देर के शिकार'

देश में कम से कम 826 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को करीब तीन से चार साल तक की देरी का सामना करना पड़ रहा है। यह बात एक स्टडी में कही गई है। इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम की स्टडी के मुताबिक, दिसंबर 2016 के आखिर तक 2,300 से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स डिवेलप किए जा रहे थे, इनमें से 826 हाउसिंग और 60 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को ठीक-ठाक देरी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में सबसे ज्यादा 48 महीने की देरी देखने को मिली है। इसके बाद तेलंगाना में 45 महीने, पश्चिम बंगाल में 44 महीने, उड़ीसा में 44 महीने और हरियाणा में 44 महीने की देरी प्रोजेक्ट्स में हुई है। वहीं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट्स में 42 महीने की देरी हुई है। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट्स को हकीकत में बदलने में 39 महीने की देरी हुई, जबकि कर्नाटक में सबसे कम 31 महीने की देरी प्रोजेक्ट्स में हुई है।

राजस्थान और केरल के प्रोजेक्ट्स कर्नाटक के बराबर की देरी झेल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में औसतन 39 महीने की देरी हुई है। पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में 39.03 महीनों और प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट में 39.63 महीने की देरी हुई है। एक बयान में कहा गया है, 'रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई रेगुलेटर्स और अथॉरिटीज से जरूरी मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में काफी समय और कॉस्ट लगती है। प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में होने वाली यह देरी न केवल हाउसिंग सेक्टर में इनवेस्टमेंट्स को हतोत्साहित करती है, बल्कि इससे देरी के साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा को मिलता है।'

एसोचैम ने कहा है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक सिंगल-विंडो सिस्टम लाना चाहिए। सरकार को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के रेगुलेटर के बजाय फेसिलिटेटर के रूप में काम करना चाहिए।

Hindustan 10 April, 2017

# आवासीय प्रोजेक्ट में चार साल तक की देरी

नई दिल्ली | एजेंसियां

घर या फ्लैट खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। एक अध्ययन में यह सामने आया है कि देश में 826 आवासीय परियोजनाएं (प्रोजेक्ट्स) ऐसी हैं जिनका निर्माण कार्य तीन से चार साल तक के विलंब से चल रहा है।

उद्योग मंडल एसोचैम के अध्ययन के अनुसार दिसंबर, 2016 के अंत तक 2,300 से अधिक रीयल एस्टेट परियोजनाओं का विकास किया जा रहा था। इनमें से 826 आवासीय और 60 वाणिज्यिक परियोजनाएं अपने समय से काफी पीछे चल रही हैं।

पंजाब में परियोजनाएं सबसे अधिक 48 महीने के विलंब से चल रही हैं। तेलंगाना में परियोजनाओं में 45 महीने, पश्चिम बंगाल में 44 महीने, ओडिशा में 44 महीने और हरियाणा में 44 महीने का विलंब है। इसी तरह मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में रीयल एस्टेट परियोजनाओं में 42 महीने का विलंब है। आवासीय परियोजना क्रियान्वयन के मामले में महाराष्ट्र में 39 महीने और कनार्टक में सबसे कम 31 महीने का विलंब है।

राजस्थान और केरल में परियोजनाएं भी केरल के बराबर देरी से चल रही हैं। देशभर में औसत आधार पर रीयल एस्टेट परियोजनाओं में 39 महीने का विलंब है। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में 39.03 महीने और निजी क्षेत्र में 39.63 माह का विलंब है। जानकार मानते हैं कि ऐसे में बुकिंग करा चुके उपभोक्ताओं पर खर्च का दबाव और ज्यादा बढ़ने वाला है।

## बढ़ता भार

- देश में 826 आवासीय परियोजनाओं में निर्माण कार्य काफी धीमी रफ्तार में
- औसत आधार पर रीयल एस्टेट परियोजनाओं में 39 महीने की देरी
- उत्तर प्रदेश ,मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 42 महीने का विलंब है

Rashtriya Sahara

10 April, 2017

# हाउसिंग प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं कर रहे डेवलपर

■ नई दिल्ली।

घर खरीदने के लोगों को आवासीय परियोजनाओं में पंजीकरण के बाद कई साल बीतने के बाद भी कब्जा नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह यह है कि कई परियोजनाएं काफी विलंब से चल रही हैं।

एक अध्ययन में यह सामने आया है कि देश में 826 आवासीय परियोजनएं तीन से चार साल के विलम्ब से चल रही हैं। उद्योग मंडल एसोचैम के अध्ययन के अनुसार दिसम्बर, 2016 के अंत तक 2300 से अधिक रीयल एस्टेट परियोजनाओं का विकास किया जा रहा था। इनमें से 826 आवासीय और 60 वाणिज्यिक परियोजनाएं अपने समय से काफी पीछे चल रही हैं।

- इस समय चल रहे 2300 हाउसिंग प्रोजेक्ट
- 826 परियोजनाएं में चार साल तक का है विलंब
- साठ वाणिज्यिक परियोजनाएं भी हैं विलंबित
- पंजाब में 48 महीने के विलंब से चल रहे प्रोजेक्ट
- तेलंगाना में 45 और प.बंगाल में 44 महीने विलंबित
- ओड़िशा में 44 और हरियाणा में 44 महीने का विलंब
- यूपी में रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट में 42 महीने का विलंब

पंजाब में परियोजनाएं सबसे अधिक 48 महीने के विलंब से चल रही हैं। तेलंगाना में परियोजनाओं में 45 महीने, पश्चिम बंगाल में 44 महीने, ओड़िशा में 44 महीने और हरियाणा में 44 महीने का विलंब है। इसी तरह मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में रीयल एस्टेट परियोजनाओं में 42 महीने का विलंब है। परियोजना क्रियान्वयन के मामले में महाराष्ट्र में 39 महीने और कर्नाटक में सबसे कम 31 महीने का विलंब है।

राजस्थान और केरल में परियोजनाएं भी केरल के बराबर देरी से चल रही हैं। औसत आधार पर रीयल एस्टेट परियोजनाओं में 39 महीने का विलंब है। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में 39.03 महीनों और निजी क्षेत्र में 39.63 माह का विलंब है। ■ भाषा

Amar Ujala

10 April, 2017

# तय समय से 4 साल पीछे हैं 826 आवासीय परियोजनाएं

नई दिल्ली। देश में 826 आवासीय परियोजनाएं लगभग तीन-चार सालों की देरी का सामना कर रही हैं। यह बात एसोचैम के एक अध्ययन से सामने आई।

अध्ययन के मुताबिक, दिसंबर 2016 के अंत तक 2,300 से ज्यादा रियल एस्टेट परियोजनाएं विकसित हो रही थीं। उनमें से 826 आवासीय और 60 वाणिज्यिक परियोजनाएं काफी समय पहले तैयार हो जानी चाहिए थीं। परियोजनाएं पूरी होने में सर्वाधिक 48 माह की देरी पंजाब में देखी गई। उसके बाद तेलंगाना (45 माह), पश्चिम बंगाल (44 माह), ओडिशा (44 माह) और हरियाणा (44 माह) का स्थान रहा। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं में 42 माह की देरी दर्ज की गई। महाराष्ट्र में यह देरी 39 माह की रही, वहीं कर्नाटक में सबसे कम 31 माह की देरी दर्ज की गई। राजस्थान और केरल में रियल्टी परियोजनाओं में देरी कर्नाटक के लगभग बराबर रही।

बयान में कहा गया कि रियल एस्टेट और आवासीय क्षेत्र कई परेशानियों से जूझ रहा है। कई नियामकों और प्राधिकरणों से अनिवार्य मंजूरियां लेने की प्रक्रिया में अत्यधिक लागत और समय लगता है। यह आवासीय क्षेत्र में न केवल निवेश को हतोत्साहित करता है बल्कि परियोजनाओं में देरी और भ्रष्टाचार को भी जन्म देता है। एसोचैम के मुताबिक केंद्र व राज्यों को रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए एकल विंडो व्यवस्था लानी चाहिए। एजेंसी

Dainik Bhaskar

10 April, 2017

# दो लाख सस्ते घरों के 352 प्रोजेक्ट लांच

- 17 राज्यों के 53 शहरों में हैं ये प्रोजेक्ट
- 38,000 करोड़ रु. होगा इन पर निवेश
- 15-30 लाख रु. तक के फ्लैट बनेंगे

एजेंसी | नई दिल्ली/गांधीनगर

आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री वेंकैया नायडू ने रविवार को 352 हाउसिंग प्रोजेक्ट लांच किए। ये प्रोजेक्ट 17 राज्यों के 53 शहरों में हैं। इनमें 38,000 करोड़ रुपए के निवेश से 2 लाख से ज्यादा सस्ते (अफोर्डेबल) घर बनाए जाएंगे। सभी प्रोजेक्ट निजी कंपनियों के हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1.03 लाख फ्लैट के प्रोजेक्ट हैं। हर फ्लैट की लागत 15 से 30 लाख रुपए तक होगी। औसत लागत 18 लाख रुपए होगी। नायडू ने बताया कि जून 2015 में लांच प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत इससे पहले 17.73 लाख सस्ते घर बनाने को मंजूरी दी जा चुकी है। इन पर 95,660 करोड़ रु. का निवेश होगा। इन्हें बनाने के लिए 27,879 करोड़ रु. की सरकारी मदद को भी स्वीकृति मिल चुकी है। योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से एक लाख से 2.35 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है। सालाना 18 लाख रु. तक कमाई वाले इस स्कीम के दायरे में आते हैं। यह योजना 2022 तक सबको घर मुहैया कराने के मिशन का हिस्सा है।

## 826 हाउसिंग प्रोजेक्ट में चार साल तक की देरी

देश में 826 हाउसिंग और 60 कॉमर्शियल प्रोजेक्ट चार साल तक की देरी से चल रहे हैं। औसत देरी 39 महीने की है। एसोचैम ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। सबसे ज्यादा लेट पंजाब के प्रोजेक्ट हैं। यहां के प्रोजेक्ट 48 माह, तेलंगाना के 45, पश्चिम बंगाल के 44, ओडिशा और हरियाणा के 44, मध्य प्रदेश, आंध्र और यूपी के 42, महाराष्ट्र के 39 और कर्नाटक, राजस्थान और केरल के प्रोजेक्ट 31 की देरी से चल रहे हैं।

## जेपी इन्फ्रा के एमडी समेत 4 के खिलाफ शिकायत दर्ज

एक खरीदार की शिकायत पर जेपी इन्फ्राटेक के एमडी समेत चार अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनमें एमडी मनोज गौर, ज्वाइंट एमडी समीर गौर, सीनियर चीफ मैनेजर राजीव तलवार और चीफ मैनेजर मनोज शामिल हैं। गाजियाबाद के निखिल चंदेल ने दनकौर थाने में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि निखिल ने स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में 2013 में फ्लैट बुक कराया था। बिल्डर ने तीन साल में पजेशन का आश्वासन दिया, लेकिन तीन साल में कंस्ट्रक्शन तक शुरू नहीं हुआ। प्रोजेक्ट के लेआउट को मंजूरी तक नहीं मिली है। निखिल ने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, उसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई।

Navodaya Times

10 April, 2017

# 826 हाऊसिंग प्रोजैक्ट्स में 4 वर्ष तक का विलम्ब

नई दिल्ली, 9 अप्रैल (एजैंसी): घर खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है।

एक स्टडी में यह सामने आया है कि देश में 826 आवासीय परियोजनाएं (हाऊसिंग प्रोजैक्ट्स) 3 से 4 वर्ष के विलम्ब से चल रही हैं। उद्योग मंडल एसोचैम की स्टडी अनुसार दिसम्बर, 2016 के अंत तक 2300 से अधिक रियल एस्टेट प्रोजैक्टों का विकास किया जा रहा था। इनमें से 826 हाऊसिंग और 60 कमर्शियल प्रोजैक्ट अपने समय से काफी पीछे चल रहे हैं।

## पंजाब में सबसे अधिक विलम्ब

पंजाब में प्रोजैक्ट सबसे अधिक 48 माह के विलम्ब से चल रहे हैं। तेलंगाना में परियोजनाओं में 45 माह, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और हरियाणा में 44-44 माह का विलम्ब है। इसी तरह मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में 42 माह का विलम्ब है। प्रोजैक्ट एग्जीक्यूशन मामले में महाराष्ट्र में 39 माह और कर्नाटक में सबसे कम 31 माह का विलम्ब है। राजस्थान और केरल में परियोजनाएं भी केरल के बराबर देरी से चल रही हैं। औसत आधार पर रियल एस्टेट प्रोजैक्टों में 39 माह का विलम्ब है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोजैक्टों में 39.03 महीनों और निजी में 39.63 माह का विलम्ब है।

Naya India

10 April, 2017

# देश में 826 आवासीय परियोजनाएं में चार साल की देरी

**नई दिल्ली, भाषा।** घर खरीदने के लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। एक अध्ययन में यह सामने आया है कि देश में 826 आवासीय परियोजनएं तीन से चार साल के विलंब से चल रही हैं। उद्योग मंडल एसोचैम के अध्ययन के अनुसार दिसंबर, 2016 के अंत तक 2,300 से अधिक रीयल एस्टेट परियोजनाओं का विकास किया जा रहा था। इनमें से 826 आवासीय और 60 वाणिज्यिक परियोजनाएं अपने समय से काफी पीछे चल रही हैं। पंजाब में परियोजनाएं सबसे अधिक 48 महीने के विलंब से चल रही हैं। तेलंगाना में परियोजनाओं में 45 महीने, पश्चिम बंगाल में 44 महीने, ओड़िशा में 44 महीने और हरियाणा में 44 महीने का विलंब है। इसी तरह मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में रीयल एस्टेट परियोजनाओं में 42 महीने का विलंब है। परियोजना क्रियान्वयन के मामले में महाराष्ट्र में 39 महीने और कर्नाटक में सबसे कम 31 महीने का विलंब है। राजस्थान और केरल में परियोजनाएं भी केरल के बराबर देरी से चल रही हैं।